भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 615
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025

ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई हॉटस्पाट / एफटीटीएच सेवाएं

615. डॉ. भोला सिंहः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से भारतनेट परियोजना के अंतर्गत जुड़े ग्राम पंचायतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेस पर इंटरनेट के उपयोग और इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उन ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या क्या है, जहां उक्त परियोजना के अंतर्गत वाई-फाई हॉटस्पॉट या एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) सेवाएं सक्षम की गई हैं;
(घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ती और अंतिम छोर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, और
(ङ) क्या कम डिजिटल पहुँच वाले पिछड़े जिलों में भारतनेट चरण-III का विस्तार करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना का चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जा रहा है, अब तक 2,14,325 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेवा प्रदान कराने के लिए तैयार किया गया है। देश में सेवा प्रदान करने के लिए तैयार की गई ग्राम पंचायतों (जीपी) का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) जी हाँ, बीएसएनएल ने भारतनेट नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शनों के कार्यान्वयन हेतु पायलट परियोजना के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए मार्च-अप्रैल 2024 के दौरान थर्ड-पार्टी ऑडिट करवाया। ऑडिट के निष्कर्षों से पता चला कि

बीएनयू साझेदारों द्वारा संस्थापित ओएलटी के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफटीटीएच सेवाओं की कवरेज संतोषजनक है।

(ग) भारतनेट परियोजना के अंतर्गत कुल 1,04,574 वाई-फाई हॉटस्पॉट संस्थापित किए गए हैं और दिनांक 30.06.2025 तक 13,01,193 फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) संशोधित भारतनेट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वहनीयता और लास्ट माइल (अंतिम छोर) कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 1.5 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन को रोल आउट करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

(ङ) शेष ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना तथा नेटवर्क को सुदृढ़ करना संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के कार्यक्षेत्र में आता है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) में राज्य के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों सहित मांग के आधार पर बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना भी शामिल है।

अनुबंध-I

लोक सभा के दिनांक 23.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 615 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में सेवा उपलब्ध कराने के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्य-वार विवरण

क्रं.सं.	राज्य	सेवा के लिए तैयार कुल ग्राम पंचायतें
1.	अंडमान एवं निकोबार	72
2.	आंध्र प्रदेश	12,955
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,124
4.	असम	1,507
5.	बिहार	8,340
6.	चंडीगढ	12
7.	छत्तीसगढ	9,695
8.	दादरा और नगर हवेली	20
9.	दमन एवं दीव	18
10.	गोवा	-
11.	गुजरात	14,320
12.	हरियाणा	6,082
13.	हिमाचल प्रदेश	410
14.	जम्मू और कश्मीर	1,101
15.	झारखंड	4,390
16.	कर्नाटक	6,084
17.	केरल	978
18.	लद्दाख	193
19.	लक्षद्वीप	9
20.	मध्य प्रदेश	17,850
21.	महाराष्ट्र	24,575
22.	मणिपुर	1,475
23.	मेघालय	698
24.	मिजोरम	540
25.	नागालैंड	236

26.	ओडिशा	6,785
27.	पुदुचेरी	98
28.	पंजाब	12,668
29.	राजस्थान	8,776
30.	सिक्किम	35
31.	तमिलनाडू	10,298
32.	तेलंगाना	10,825
33.	त्रिपुरा	740
34.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	34,274
35.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	12,472
36.	उत्तराखंड	1,993
37.	पश्चिम बंगाल	2,677
	कुल	**2,14,325**

****